बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : अवलोकन

- हाल के वर्षों में, बिहार ने विकास के मोर्चे पर अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पूरे देश और यहां तक कि विदेशों में भी काफी ध्यान आकर्षित किया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार, 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 10.5 प्रतिशत (स्थिर कीमतों पर) थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर से अधिक है।
- 2019-20 में बिहार का GSDP मौजूदा कीमतों पर 6,11,804 करोड़ रुपये और स्थिर (2011-12) कीमतों पर 4,14,977 करोड़ रुपये था। राज्य के लिए NSDP 2019-20 में मौजूदा कीमतों पर 5,62,710 करोड़ रुपये और स्थिर कीमतों पर 3,77,276 करोड़ रुपये था। बिहार की परिणामी प्रति व्यक्ति GSDP मौजूदा कीमतों पर 50,735 रुपये और स्थिर (2011-12) कीमतों पर 34,413 रुपये थी।
- द्वितीयक क्षेत्र ने 4.8 प्रतिशत (2017-18) से 14.3 प्रतिशत (2016-17) के बीच उतार-चढ़ाव वाली वृद्धि दर दर्ज की है। द्वितीयक क्षेत्रों के भीतर, दो उप-क्षेत्रों ने उच्च विकास दर दर्ज की - EGWUS (बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं) और निर्माण। 2019-20 के दौरान, प्रथम ने 20.3 प्रतिशत और दूसरे ने 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की थी। तृतीयक क्षेत्र के भीतर, तीन उप-क्षेत्र हैं - सड़क परिवहन, परिवहन और लोक प्रशासन से संबंधित सेवाएं, जिन्होंने 2018-19 और 2019-20 दोनों में दो अंकों की वृद्धि दर दर्ज की थी ।
- तीन प्रमुख क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक) में, जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2013-14 में 23.4 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 19.5 प्रतिशत हो गई है। द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है- 2013-14 में 19.3 प्रतिशत से 2019-20 में 20.3 प्रतिशत। यह वास्तव में तृतीयक क्षेत्र है जिसने अपने हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो 2013-14 में 57.3 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 60.2 प्रतिशत हो गया है।
- 2017-18 में प्रति व्यक्ति GSDP के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग से पता चलता है कि बिहार में तीन सबसे समृद्ध जिले हैं - पटना (1,12,604 रुपये), बेगूसराय (45,540 रुपये) और मुंगेर (रु. 37,385)। दूसरे छोर पर सबसे अधिक गरीब जिले हैं- किशनगंज (19,313 रुपये), अररिया (18,981 रुपये) और शिवहर (17,569 रुपये)।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-02 : राज्य वित्त

- राज्य ने एक दशक से अधिक समय से लगातार राजकोषीय विवेक दिखाया है और वित्तीय संकेतक बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार में राज्य के वित्त के साधन खर्च के दिए गए स्तर के लिए टिकाऊ हैं। GSDP के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 2.0 प्रतिशत था और राजस्व खाता 2019-20 के दौरान अधिशेष में रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में प्राथमिक घाटा घट गया।
- वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के वित्तीय संकेतक इंगित करते हैं कि राज्य सरकार के साधन वर्ष के दौरान व्यय के स्तर के लिए टिकाऊ हैं। 2019-20 के दौरान पूरे देश में आर्थिक मंदी का असर देखा गया, जिससे राज्य और केंद्र सरकार दोनों के राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,53,408 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2018-19 के दौरान 1,52,287 करोड़ रुपये से मामूली अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार में राज्य सरकार का कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय क्रमश: 1,23,533 करोड़ रुपये और 20,080 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार का कुल व्यय 2019-20 में 7.1 प्रतिशत घटकर पिछले वर्ष की तुलना में 1,43,613 करोड़ रुपये रहा।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-03 : कृषि और संबद्ध क्षेत्र

- 2019-20 में, राज्य के जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का कुल योगदान 18.7 प्रतिशत रहा। 2018-19 में 144 प्रतिशत की फसल तीव्रता के साथ सकल फसली क्षेत्र 74.06 लाख हेक्टेयर था। 2019-20 में बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में 163.80 लाख टन का पर्याप्त रिकॉर्ड दर्ज किया।
- बिहार का कुल दुग्ध उत्पादन 2019-20 में बढ़कर 104.83 लाख टन हो गया, जो 2015-16 में 82.88 लाख टन था, जो 6.07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर को दर्शाता है।
- 2018-19 में सकल सिंचित क्षेत्र 54.93 लाख हेक्टेयर था। सात निश्चय-2 (हर खेत को पानी) के तहत राज्य सरकार की योजना राज्य के हर खेत की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की है। लघु जल संसाधन विभाग ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत अहार-पाइन्स, तालाब, चेक-डैम और लिफ्ट सिंचाई की कुल 1659 योजनाओं को हाथ में लिया है।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-04 : उद्यम क्षेत्र

- निर्माण उप-क्षेत्र बिहार में वर्षों से विकास का प्रमुख चालक रहा है, इसके बाद EGWUS (बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं) का स्थान है। इसके अलावा, अखिल भारतीय

BYJU'S EXAM PREP
SUBSCRIBE BYJU'S EXAM PREP

औसत लगभग 31 प्रतिशत की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है।

- 2007-08 और 2017-18 के बीच कृषि आधारित कारखानों के संचालन की वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत तक रही है, जो अखिल भारतीय स्तर की तुलना में 9.3 प्रतिशत अंक अधिक थी। कृषि आधारित कारखानों की संख्या में वृद्धि से पता चलता है कि बिहार के कृषि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अब वास्तव में राज्य के भीतर संसाधित होता है।
- पिछले तीन वर्षों के लिए असिंचित गैर-कृषि उद्यमों (UNAE) की वृद्धि का आकलन किया गया, बिहार में 36.2 प्रतिशत उद्यमों ने पिछले तीन वर्षों में विस्तार दर्ज किया है, जो अखिल भारतीय स्तर से 7.6 प्रतिशत अधिक था।
- 2019-20 में 674.05 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया। चीनी रिकवरी दर 2018-19 में 10.37 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 10.72 प्रतिशत हो गई।
- पिछले कुछ वर्षों में, बिहार में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। 2018-19 और 2019-20 के बीच, कार्यान्वयन एजेंसियों में लक्षित लाभार्थियों की संख्या में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2018-19 से 2019-20 के बीच वित्तीय लक्ष्य में भी 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय- 05: श्रम, रोजगार और प्रवासन

- पुरुष और महिला दोनों कामगारों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR) भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार में सबसे कम था। महिला डब्ल्यूपीआर ग्रामीण बिहार में 4.0 प्रतिशत और शहरी बिहार में 5.7 प्रतिशत थी।
- बिहार में नियमित वेतन/वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों का अनुपात केवल 9.7 प्रतिशत था, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम था।
- कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में 47.9 प्रतिशत पुरुष श्रमिकों और 66.8 प्रतिशत महिला श्रमिकों को शामिल किया गया। महिला श्रमिकों के लिए, कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के बाद, 16.7 प्रतिशत पर शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता थी।
- कोविड-19 के दौरान, राज्य सरकार ने प्रत्येक निर्माण श्रमिक के लिए 2000 रुपये के अनुदान की घोषणा की। 31 अगस्त, 2020 तक, 11,07,696 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीच रु. 221.54 करोड़ का वितरण किया गया।
- कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य में

औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित अवधि योजना जोड़कर श्रम कानूनों में संशोधन किया है और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन, बिहार संशोधन) मैनुअल, 2020 में श्रमिकों की सीमा 20 से 50 तक वृद्धि करने के लिए संशोधन किया है।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-06: अवसंरचना एवं संचार

- जीएसडीपी में निर्माण क्षेत्र का योगदान 1980-81 में 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 6.2 प्रतिशत हो गया और 1995-96 में 3.4 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर आ गया। 2005 से राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश के बाद, 2005-10 की अवधि के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जब 2009-10 में यह बढ़कर 11.9 प्रतिशत हो गया। यह अभी भी जीएसडीपी में 10 प्रतिशत का योगदान देता है।
- बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) हैं, जिनकी लंबाई सितंबर, 2020 तक 5475 किलोमीटर है, जो 2005 की लंबाई से लगभग 1940 किलोमीटर अधिक है। पिछले 15 वर्षों के दौरान, राज्य में 30 और राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए हैं।
- 2005 तक गंगा नदी पर केवल 4 पुल थे।
- मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना (MMKSUCY) के तहत, राज्य सरकार ने शहद, रेडीमेड अनाज आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समूहों की स्थापना के माध्यम से पांच जिलों (गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी) को प्रोत्साहित किया है।
- परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों से लौट रहे 25 लाख से अधिक मजदूरों के परिवहन, उनके कौशल मानचित्रण और क्षेत्रीय वितरण (लाल, नारंगी और हरा) के माध्यम से कोविड -19 के दौरान गंभीर स्थिति का प्रबंधन किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोविड -19 के दौरान शहरी परिवहन में नवाचारों के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार को सराहनीय पहल का पुरस्कार प्रदान किया।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-07: ऊर्जा क्षेत्र

- राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 145 kwh से बढ़कर 2019-20 में 332 kwh हो गई है, जिसका अर्थ है कि पिछले सात वर्षों में 129 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- राज्य में उपलब्ध विद्युत क्षमता 2018-19 में 4767 मेगावाट थी, जो 2019-20 में बढ़कर 6073 मेगावाट हो गई, जिसका अर्थ 27.4 प्रतिशत की वृद्धि है। राज्य सरकार ने पहले ही विभिन्न स्रोतों से 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से 4516 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए योजना बनाई है।

- बिहार में वितरण प्रणाली दो वितरण कंपनियों - नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) द्वारा संचालित की जा रही है।
- बिहार में विद्युत का उत्पादन और खरीद (नेट केंद्रीय पारेषण हानि) 2016-17 में 23,027 एमयू से बढ़कर 2019-20 में 30,630 एमयू हो गया, जिसका अर्थ है कि तीन वर्षों में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
- मार्च 2019 तक बिजली की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 27.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 4767 मेगावाट थी; मार्च 2020 के दौरान यह 6073 मेगावाट तक पहुंच गया है। मार्च 2019 से मार्च 2020 के दौरान, कोयला आधारित ताप विद्युत में वृद्धि दर 21.7 प्रतिशत, जल विद्युत में 50.6 प्रतिशत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 58.0 प्रतिशत है।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-08 : ग्रामीण विकास

- बिहार आजीविका मिशन (जीविका) राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। 2015-16 में 4.70 लाख की तुलना में वर्तमान में गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10.17 लाख है। इन स्वयं सहायता समूहों को 2019-20 में 13.14 हजार करोड़ 2019-20 में 13.14 हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है, जो रु. 2015-16 में 1.30 हजार करोड़ रु. था।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) ग्रामीण गरीबों के लिए आवास सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। 2019-20 में, 8210.90 करोड़ रुपये की लागत से 4.2 लाख घरों का निर्माण किया गया।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। अब तक, इसने 1.09 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHL) का निर्माण किया है। वर्तमान में 96 प्रतिशत गांव खुले में शौच मुक्त (ODF) हो चुके हैं।
- शहरी कार्यक्रम 25-50 हजार आबादी वाले गांवों के समूह में शहरी सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। इस कार्यक्रम के लिए बिहार में 11 समूहों की पहचान की गई थी। अब तक मिशन के लिए 1179.7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-09 : शहरी विकास

- बिहार में, अखिल भारतीय स्तर की तुलना में शहरीकरण की दर कम (11.3 प्रतिशत) रही है। लेकिन हाल ही में, 8 नई नगर परिषदों के साथ-साथ 109 नई अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, 32 पुरानी अधिसूचित क्षेत्र परिषदों को नगर परिषदों में

SUBSCRIBE

अपग्रेड किया गया है, जबकि 5 पुरानी नगर परिषदों को नगर निगमों में अपग्रेड किया गया है। 12 नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है। परिणामस्वरूप, शहरीकरण की दर 11.3 से बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो गई है।

- राज्य सरकार ने 2020-21 तक शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में पानी की पाइपलाइन कनेक्शन के साथ स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'हर घर नल का जल' योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन सभी हैंडपंपों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिन पर शहरी लोग अपनी पानी की जरूरत के लिए निर्भर हैं। मोटे तौर पर अनुमान है कि इस कार्यक्रम के तहत लगभग 15.854 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
- बिहार में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (SHG) की संख्या 2017-18 में 2185 से बढ़कर 2019-20 में 4542 हो गई है। NULM के तहत SHG में सदस्यों की संख्या भी 2017-18 में 21,850 से बढ़कर 2019-20 में 42,351 हो गई।
- 142 शहरी केंद्रों और 3367 वार्डों में से कुल 3367 वार्डों को ODF (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-10 : बैंकिंग और संबद्ध क्षेत्र

- पूर्णिया में सर्वाधिक सीडी अनुपात 75.1 प्रतिशत और मुंगेर में सबसे कम 25.9 प्रतिशत है। किशनगंज 60.6 प्रतिशत सीडी अनुपात के साथ दूसरे स्थान पर है। मुंगेर, सारण, भोजपुर और अरवल ऐसे जिले हैं जिनका सीडी अनुपात 30 प्रतिशत से भी कम है।
- मार्च 2020 तक बिहार में सभी बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) कुल अग्रिमों का 14.9 प्रतिशत थी, जो मार्च 2019 तक 10.9 प्रतिशत से अधिक है।
- बिहार के लिए मुद्रा ऋण का लक्ष्य 2019-20 में बढ़कर 9531.12 करोड़ रुपये हो गया, जो 2018-19 में 4170.5 करोड़ रुपये था। स्वीकृत ऋणों की संख्या भी 2019-20 में 7458.0 करोड़ रुपये से बढ़कर 8698.89 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2019-20 (99.0 प्रतिशत) के दौरान 'शिशु' श्रेणी के ऋणों के लिए उपलब्धि प्रतिशत सबसे अधिक था।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-11: मानव विकास

- राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में अपने विकास व्यय में वृद्धि की है। पिछले छः वर्षों (2014-15 से 2019-20) के दौरान, बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय (PCDE) 17.9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि समग्र रूप से देश के लिए यह कम दर 11.6 प्रतिशत से बढ़ रहा है। शिक्षा पर व्यय की वृद्धि दर क्रमशः 17.3 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर 21.4 प्रतिशत थी।

- बिहार के लिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, कुल प्रजनन दर (TFR), जो 2001 में प्रति महिला 4.4 जन्म हुआ करती थी, 2011 में घटकर 3.6 और 2016 में 3.3 हो गई है। बिहार के लिए जीवन प्रत्याशा (LEB) ने 2006-10 में 65.8 वर्ष से 2014-18 में 69.1 वर्ष की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। 2014-18 के दौरान, भारत में LEB 0.3 वर्ष अधिक (69.4 वर्ष) था।
- 2019-20 में जल गुणवत्ता की समस्याओं को हल करने के लिए, कुल 37,911 वार्डों को मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत कवर किया गया था। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) के निर्माण में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। 2017-18 (34.3 लाख) और 2018-19 (61.3 लाख) में योजना की उपलब्धि बकाया थी।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक पास करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को 10,000 रुपये और रुपये 15,000 मुस्लिम लड़कियों को, जो प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट पास करती हैं, सतत शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-12 : बाल विकास

- बिहार में 48 प्रतिशत जनसंख्या 0-18 वर्ष के आयु वर्ग में है। राज्य में 4.98 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 4.47 करोड़ (89.9 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में और 0.50 करोड़ (10.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- 0-18 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 883 महिलाओं से बढ़कर 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 897 महिलाएं हो गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, 0-18 आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात वर्ष प्रति 1000 पुरुषों पर क्रमशः 899 और 929 महिलाएं थीं। किशोरियों के लिए योजना (SAG) 11 से 14 वर्ष के बीच की लड़कियों के लिए है जो स्कूल नहीं जा रही हैं।
- बिहार के लिए साक्षरता दर 2011 में 61.8 प्रतिशत थी, जो 2001 में 47.0 प्रतिशत से बढ़कर 14.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। हालांकि, बच्चों (7-18 वर्ष) में साक्षरता दर 79.1 प्रतिशत है और 2011 में इस आयु वर्ग के लिए लिंग अंतर 5.4 प्रतिशत अंक है।
- शिक्षा विभाग, बिहार ने कक्षा IX-X के छात्रों के लिए अप्रैल, 2020 से, कक्षा VI-VIII के साथ-साथ कक्षा XI-XII के लिए मई, 2020 से और कक्षा I-II के साथ-साथ कक्षा III -V के लिए जून, 2020 से ई-कंटेंट का प्रसारण DD बिहार के माध्यम से शुरू किया।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय-13: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन

- बिहार में कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और लॉगिंग का योगदान पिछले पांच वर्षों में औसतन लगभग 7.9 प्रतिशत रहा। 2019-20 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कुल वर्ष के दौरान कृषि वानिकी और हरियाली मिशन के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 116.17 करोड़ रुपये थे।
- पक्षी संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बिहार का पहला राज्य पक्षी उत्सव, 'कलरव' 15-17 जनवरी, 2021 को जमुई के नागी व नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था। तीन दिवसीय पक्षी उत्सव के लिए कुल बजट रु. 85 लाख था।
- लॉकडाउन के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे बिहार के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1000 रुपये प्रति राशन कार्ड धारक को कोरोना सहायता के रूप में 1624.39 करोड़ भुगतान किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण लेख

67th BPSC/CDPO Bihar Special: Geography Preparation Tips, Strategy and Study Material (Free PDF)
67th BPSC/CDPO Bihar Special: Polity Preparation Tips, Strategy and Study Material (Free PDF)
67th BPSC/CDPO Bihar Special: Environment & Ecology Strategy and Study Material (Free PDF)
67th BPSC/CDPO Bihar Special: Art and Culture Preparation Strategy and Study Material (Free PDF)
67th BPSC/CDPO Bihar Special: CSAT Preparation Tips, Strategy and Study Material (Free PDF)
67th BPSC/CDPO Bihar Special: History Preparation Tips, Strategy and Study Material (Free PDF)
67th BPSC/CDPO Bihar Special: Economy Preparation Tips, Strategy and Study Material (Free PDF)
67th BPSC/CDPO Bihar Special: Monthly Current Affairs Magazine (Free PDF)
Surprise 🥳🎁 | 67th BPSC/CDPO सुदर्शन चक्र: Complete Study Material Package Free PDFs
Improve Your Writing Skill Via Joining: Weekly Writing Competition
One-liners: Get Complete Highlights of the Day